राष्ट्रपति क्यों झूठ बोल रहे हैं कि सीएए लागू कर 'उनकी' सरकार ने गांधी जी का सपना किया है पूरा

माननीय राष्ट्रपति महोदय को बताना चाहिए कि जिन गांधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता और आपसी खून खराबा रोकने के लिए लम्बा उपवास किया हो, उसका ऐसा कुत्सित सपना कैसे हो सकता है...

महेंद्र पाण्डेय

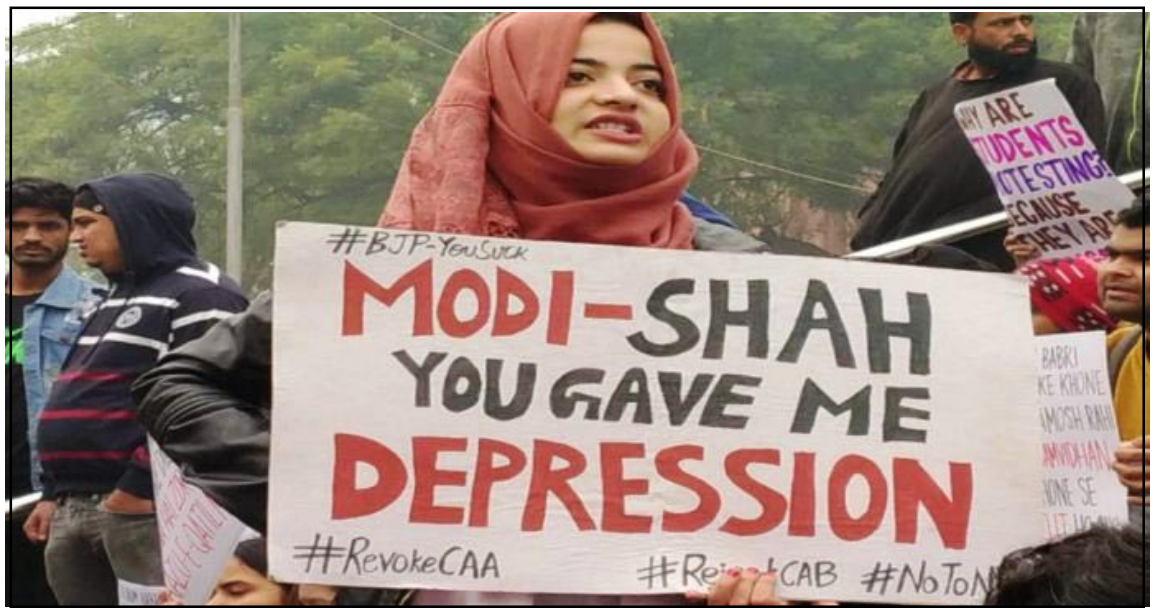

दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में ऐसा पहली बार हो रहा होगा, जब जनता सहिष्णु है और सत्तापक्ष असहिष्णु हो चला है और भयभीत भी। इतना भयभीत कि झूठ को छोड़ भी दें तब भी हिंसा भड़काने पर उतारू हो चला है और अब तो मुख्यमंत्री को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है।

दिल्ली के चुनाव की शुरुवात टुकडे-टुकडे गैंग की याद दिलाकर सत्ता पक्ष ने किया था। इसके ठीक बाद यशवंत सिन्हा ने किसी सभा में कहा था कि देश में टूकडे-टूकडे गैंग है जिसके दो ही सदस्य हैं और दोनों बीजेपी में हैं। बीजेपी के पूरी दिल्ली में बिखरे पड़े होर्डिंग्स को भी देखिये तो टुकडे-टुकडे गैंग वाली मानसिकता सीधे समझ में आती है।

इसमें लिखा है, "देश बदला, अब दिल्ली बदलो"। इसे पढ़कर कोई भी यही प्रश्न पूछेगा कि क्या दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है? ऐसी ही भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी किया गया था। क्या, जहां चुनाव होते हैं वह हिस्सा देश का नहीं रहता, इस सवाल का जवाब असली और खांटी टुकडे-टुकडे गैंग से जरूर माँगा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों के बीच बालाकोट का राग अलापा था, और इस बार बिना किसी सन्दर्भ के यह बताते हैं कि पाकिस्तान को हम केवल 7 से 10 दिनों में हराने की क्षमता रखते हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को हारने और बांग्लादेश के जन्म में महज 13 दिनों का समय लगा था।

ध्यान रहे कि उस समय ना तो इतनी संख्या में सेना थी और ना ही सेना के पास आज जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। सेना तो उस दौर में टेक्नोलॉजी का सहारा भी नहीं था और ना ही सॅटॅलाइट चित्रों से विपक्षी सेना की गतिविधियों की निगरानी की जा सकती थी। उस समय सही में बादलों के बीच से राडार विमानों पर नजर नहीं रख पाता था। अगर 1971 में महज 13 दिनों में युद्ध जीता गया तो आज के 10 दिनों में युद्ध जीतने की बात अजीब लगती है, पर प्रधानमंत्री जी इसे ब्रेकिंग न्यूज जैसा प्रचारित करते रहे और मीडिया भी इसे कवर स्टोरी बनाता रहा।

सीएए-एनआरजी शाहीन बाग और फिर दिल्ली के चुनावों में गांधी जी की चर्चा खूब की गयी। पहले तो राष्ट्रपति की सरकार (राष्ट्रपति हरेक अभिभाषण में मेरी सरकार कहते हैं) के मुखिया ने गांधी जी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, पर अब तो राष्ट्रपति भी उसी राह पर आ गए हैं। राष्ट्रपति ने संसद में अभिभाषण के दौरान कहा कि **सीएए** को लागू कर उनकी सरकार ने गांधी जी का सपना पूरा किया है। क्या आपको लगता है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता और आपसी खून खराबा रोकने के लिए जिसने लम्बा उपवास किया हो, उसका ऐसा कुत्सित सपना हो सकता है?

26 सितंबर, 1947 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के भाषण में कहा था, 'अगर न्याय के रास्ते पर चलते हुए सभी हिंदू और मुसलमान मर भी जाएं तो मुझे परेशानी नहीं होगी। अगर ये साबित हो जाए कि भारत में रहने वाले साढ़े चार करोड़ मुसलमान छिपे रूप से देश के ख़िलाफ काम करते हैं तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उन्हें गोली मार देनी चाहिए। ठीक इसी तरह अगर पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी यही होना चाहिए। हम पक्षपात नहीं कर सकते। अगर हम अपने मुसलमानों को अपना नहीं मानेंगे तो क्या पाकिस्तान हिंदू और सिख लोगों को अपना मानेगा? ऐसा नहीं होगा।'

उन्होंने कहा था, 'पाकिस्तान में रह रहे हिंदू-सिख अगर उस देश में नहीं रहना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं। इस स्थिति में ये भारत सरकार का पहला दायित्व होगा कि उन्हें रोज़गार मिले और उनका जीवन आरामदायक होद्य लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भारत की जासूसी करें और हमारे लिए काम करें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और मैं ऐसा करने के सख्त खिलाफ़ हूं।'

इससे पहले आठ अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने 'भारत और भारतीयता' पर जो कहा वो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है – 'हिंदुस्तान हर उस इंसान का है जो यहां पैदा हुआ और यहां पला-बढ़ाद्य जिसके पास कोई देश नहीं, जो किसी देश को अपना नहीं कह सकता उसका भी। इसलिए भारत पासरी, बेनी इसराइली, भारतीय ईसाई सबका है। स्वाधीन भारत हिंदूराज नहीं, भारतीय राज होगा जो किसी धर्म, संप्रदाय या वर्ग विशेष के बहुसंख्यक होने पर आधारित नहीं होगा, बल्कि किसी भी धार्मिक भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिनिधियों पर आधारित होगा।'

अमेरिका में वॉक्स न्यूज ने दो वर्ष पहले डेविड फारिस के इंटरव्यू को प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, "व्हाई दिस पोलिटिकल साइंटिस्ट थिंक्स द डेमोक्रेट्स हैव टू फाइट डर्टी"। डेविड फारिस रूवेल्ट यूनिवर्सिटी में राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, और एक पुस्तक प्रकाशित की है, इट इस टाइम टू फाइट डर्टी। अमेरिका में इस पुस्तक की बहुत चर्चा है और इसमें कहा गया है कि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को परम्परागत राजनीति से नहीं हटाया जा सकता है, इसे हटाने के लिए ओछी राजनीति की जरूरत है। इस पुस्तक में भी यदि आप इसके आलेख से रिपब्लिकन के बदले अपने देश की सत्ताधारी पार्टी का नाम शामिल कर लें तो यह पुस्तक शत-प्रतिशत हमारे देश पर सटीक बैठती है।

डेविड फारिस बताते हैं, हम इस समय अमेरिका के पूरे इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर हैं। इस समय संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा उठ चुका है और लोग चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाने लगे हैं। ट्रम्प प्रशासन देश को राजनैतिक संस्कृति और परंपरा को खतरनाक तरीके से बदलने में कामयाब रहा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी केवल नीतियों की लड़ाई नहीं लड़ सकती। अनेक सामाजिक और राजनीतिक अध्ययनों के अनुसार आज के दौर में नीतियां चुनाव में कोई मायने नहीं रखतीं और अधिकतर लोग नीतियों के प्रभाव से अनजान बने रहते हैं।

डर्टी पॉलिटिक्स के लिए वैसी सोच बनाना बहुत जरूरी है, पर ऐसा कर पाना हमारे देश में कठिन है। यदि सत्ता पक्ष के नेताओं के भाषण का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि 75 प्रतिशत से अधिक भाषण विपक्ष को कोसने में, 15 प्रतिशत गांधी-नेहरु में और 10 प्रतिशत से कम हिस्सा वो क्या कर रहे हैं, इसपर केन्द्रित होता है।

ऐसे में, विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना पूरी तरह से कुछ महीनों के लिए बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी आलोचना के कुछ वाक्य सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के भाषण का 75 प्रतिशत हिस्सा होते हैं। ऐसे में संभवत: सत्ता पक्ष के नेताओं के भाषण का समीकरण भी बदल जाएगा। पूरे विपक्ष को दीर्घकालीन रणनीति बनाकर वापस कुछ वर्षों के लिए जनता के बीच जाकर समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा।

संघ के रामराज्य का मतलब धर्म, सत्ता और संपत्ति पर ब्राह्मणों का कब्जा!

महेंद्र मिश्र

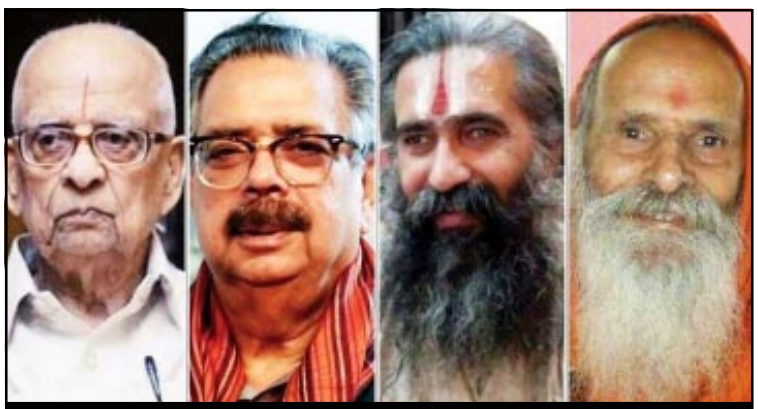

राम मंदिर ट्रस्ट : सवर्णों का जमावड़ा और परस्पर जूतम पैजार

दिल्ली चुनाव से ठीक पहले संसद के भीतर राम मंदिर के लिए न्यास और उसके सदस्यों की घोषणा कर पीएम मोदी ने आखिरी तौर पर राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की। चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंग देने की यह उनकी आखिरी कोशिश थी। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी शाहीन बाग-शाहीन बाग करती रही। इससे इतर दूसरा शब्द उसके नेताओं की जुबान पर आया ही नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा उसी कड़ी का एक और हिस्सा था। लेकिन हम यहां बात आज दिल्ली चुनाव और उसमें बीजेपी के सांप्रादियक खेल की नहीं करेंगे।

हम बात बीजेपी-संघ के उन मंसूबों की करेंगे जिसको वे इन मुद्दों के जरिये हासिल करना चाहते हैं। घोषित राम मंदिर ट्रस्ट महज कुछ नामों का समूह नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाले संघ के सपनों के समाज का प्रकृत रूप है जिसको पूरे समाज पर लागू किया जाना है। ट्रस्ट के 9 सदस्यों में अपवाद स्वरूप कामेश्वर चौपाल को छोड़कर बाकी सभी ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े तथा आदिवासी समुदाय तक के किसी एक प्रतिनिधि को इस लायक नहीं समझा गया कि वह राम मंदिर के निर्माण में हाथ बंटा सके।

कामेश्वर चौपाल दलित हैं और बिहार के सुपौल से आते हैं। बताया जाता है कि 1989 में शिलान्यास के दौरान पहली ईंट वीएचपी के तत्कालीन मुखिया अशोक सिंहल ने उन्हीं के हाथ से रखवायी थी। इसके पीछे उनका सीता के मायके मिथिलांचल से जुड़ा होना प्रमुख कारण बताया गया था। हालांकि उनकी जाति को लेकर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार मणि ने संदेह जाहिर किया है और उनका किसी अति पिछड़ी जाति से जुड़ा होना बताया जा रहा है जिसे बाद में अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की तरफ इशारा किया गया है। बहरहाल जो भी हो यह दिखाता है कि चौपाल को शामिल किया जाना बीजेपी और संघ की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक दबाव का नतीजा है। और इस बात में कोई शक नहीं कि अंदरूनी तौर पर वे चौपाल को ट्रस्टियों के एक सेवक के तौर पर ही देख रहे होंगे, जिसकी फैसलों में भूमिका नगण्य होगी।

दरअसल इसके जरिये संघ बिल्कुल साफ-साफ बताना चाहता है कि धर्म के काम में ब्राह्मणों के अलावा किसी दूसरी जाति या फिर समुदाय की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही उसमें अयोध्या के राजा के वंशज को रखकर इस बात को साफ करने की कोशिश की गयी है कि संघ की राजे-रजवाड़ों में आस्था अभी भी बरकरार है। और इससे भी आगे बढ़कर जिस तरह से कानून और चिकित्सा समेत तमाम दूसरे क्षेत्रों से भी किसी दूसरे समुदाय के किसी शख्स को रखने की जगह ब्राह्मण को ही प्राथमिकता दी गयी है। वह बताती है कि संघ के आदर्श राज्य में शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित रखा जाएगा। ट्रस्ट में किसी क्षत्रिय को न रखकर यह संदेश देने की कोशिश की गयी है कि सनातन व्यवस्था में लोगों की रक्षा का काम उनका सुरक्षित है लिहाजा उन्हें धर्म के काम से खुद को अलग ही रखना चाहिए। साथ ही रजवाड़े से भी ब्राह्मण वंशीय को रखकर यह संकेत दिया गया है कि राजा बनने और सिंहासन हासिल करने का मोह उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उनका मुख्य काम सैनिक बनकर लोगों की रक्षा करना है।

जिस राम मंदिर के लिए पिछड़ों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी उसका इस पूरी कवायद में कोई नामोनिशान तक नहीं है। कल्याण सिंह से लेकर विनय कटियार और उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान मंदिर आंदोलन के कद्दावर नेता रहे। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी जिंदा हैं और सक्रिय हैं। बावजूद इसके उन्हें ट्रस्ट का एक सदस्य बनने लायक भी नहीं समझा गया। दरअसल संघ मनुस्मृति को उसकी पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ लागू करना चाहता है। और वह इसकी इजाजत नहीं देती कि किसी धर्म के काम में पिछड़े को शामिल किया जाए। क्योंकि शास्त्रों और वर्ण व्यवस्था में उसकी भूमिका सेवक की है।

इस तरह से मंदिर आंदोलन में लाठियां भाजने और मार खाने वाले पिछड़े समुदाय को ठेंगा दिखा कर न केवल सत्ता बल्कि संपत्ति पर भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को सुनिश्चित कर दिया गया है। इस कड़ी में अब तक राम मंदिर के नाम पर आए अरबों रुपये और मंदिर निर्माण के दौरान मिलने वाली शेष भारी रकम समेत निर्माण के बाद की व्यवस्था में हर तरीके से ब्राह्मणों के लाभ को सुरक्षित कर दिया गया है। हालांकि उमा भारती ने इस पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट में पिछड़े समुदाय से भी लोगों को होना चाहिए था। उसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर डाली है।

इसके साथ ही ट्रस्ट में एक भी महिला को न रखकर इस देश की आधी आबादी को भी रामराज्य में उसकी जगह बता दी गयी है। अनायास नहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत घूम-घूम कर कहते रहते हैं कि महिलाओं की भूमिका घर की चारदीवारी के भीतर है। और उन्हें खुद को पतियों और परिवार की सेवा तक ही सीमित रखना चाहिए। उसी में उनकी मुक्ति है।

और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए (क्योंकि कोर्ट ने अयोध्या के शहरी क्षेत्र में जमीन देने का निर्देश दिया था) अयोध्या से 30 किमी दूर एक गुमनाम स्थान पर बाबरी मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन मुकर्रर कर मुसलमानों की इस देश, समाज और व्यवस्था में हैसियत बता दी गयी है। लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर स्थित रौहानी के पास धन्नीपुर में जहां यह जमीन दी जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कई मस्जिदें पहले से मौजूद हैं। लिहाजा वहां किसी नयी मस्जिद की जरूरत ही नहीं है। और इस तरह से बाबरी मस्जिद के न केवल वजूद को खारिज कर दिया गया बल्कि अब उसकी यादों को भी लोगों के जेहन से मिटाने का रास्ता साफ कर दिया गया।

इस तरह से राम मंदिर के जरिये हासिल होने वाला यही असली रामराज्य है। जिसमें सनातन धर्म की तूती बोलगी। और वर्णाश्रम व्यवस्था के मुताबिक हर जाति का अपना अधिकार और कार्य क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ या फिर उसके नियमों का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा। यह तो अभी ट्रेलर है। जब सत्ता पूरी तरह से संघ के कब्जे में आ जाएगी और देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तब नागपुर से पूरी पिक्चर रिलीज होगी। क्योंकि हिंदू तालिबान देश का नया आदर्श है। और उस सपने को संघ किसी भी कीमत पर पूरा करेगा।